भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4069
उत्तर देने की तारीख 12 अगस्त, 2026

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सेवा का विस्तार

4069. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) के एक्सेस पॉइंट, ग्राहकों और बैंकिंग आउटलेट की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में आईपीपीबी के एक्सेस पॉइंट, डोरस्टेप बैंकिंग सेवा प्रदाताओं और डिजिटल बैंकिंग लेन-देन की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार के पास बिना बैंक सुविधा वाले और कम सेवा प्राप्त ग्रामीण, जनजातीय, तटीय तथा शहरी गरीब क्षेत्रों में, विशेषकर तमिलनाडु में, आईपीपीबी सेवाओं का विस्तार करने की कोई योजना है ओर यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आईपीपीबी की अवसंरचना के विस्तार के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आईपीपीबी ग्राहकों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और प्रत्यक्ष लाभ अतंरण (डीबीटी) योजनाओं के लाभार्थियों के लिए डिजिटल संपर्क, वित्तीय साक्षरता, साइबर सुरक्षा और शिकायत निवारण में सुधार हेतु उठाए गए कदम क्या हैं?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) डाक विभाग के अधीन स्थापित इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के 649 बैंकिंग आउटलैट हैं, तथा डाकघर नेटवर्क के माध्यम से इसके 1.64 लाख एक्सेस पॉइंट हैं। इनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध - I** के रूप में संलग्न है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में आईपीपीबी के एक्सेस पॉइंट, डोर स्टेप बैंकिंग सेवा प्रदाताओं और डिजिटल बैंकिंग लेन-देन की संख्या निम्नानुसार है :

वित्तीय वर्ष	डोरस्टेप बैंकिंग सेवा प्रदाता	एक्सेस पॉइंट	डिजिटल लेन-देन	
			संख्या (करोड़ में)	मूल्य (करोड़ रु. में)
2023-24	16968	11771	1.92	3,460.74
2024-25	15406	11734	2.15	4,939.93
2025-26	15189	11658	2.24	6,219.68

(ग) आईपीपीबी सेवाएं डाकघरों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं, जो एक्सेस पॉइंट के रूप में कार्य करते हैं। अतः जब भी डाकघरों की संख्या में परिवर्तन होता है, तो आईपीपीबी के एक्सेस पॉइंट की संख्या भी स्वतः परिवर्तित हो जाती है। वर्तमान में, आईपीपीबी सेवाएं सभी डाकघरों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं, जिनमें से बहुत से डाकघर तमिलनाडु सहित, बैंकिंग सुविधाओं से वंचित, अल्पसेवित ग्रामीण, जनजातीय, तटीय तथा शहरी गरीब क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

(घ) नेट वर्थ/लीवरेज अनुपात तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन की विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में आईपीपीबी में 250 करोड़ रुपए की दो किस्तों में 500 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश किया गया था। आईपीपीबी इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए राज्य-वार अलग से कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

(ङ) आईपीपीबी ने डाकियों एवं ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) के माध्यम से प्रदान की जाने वाली कागजरहित, बायोमेट्रिक तथा फेस ऑथेंटिकेटेड डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से डिजिटल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया है। वित्तीय साक्षरता और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आईपीपीबी ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 11,926 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए हैं, जिनसे लगभग 7.75 लाख लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। इन शिविरों में सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं, साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम तथा डिजिटल वित्तीय सेवाओं के सुरक्षित उपयोग के संबंध में जागरूकता प्रदान की गई, जिसमें महिलाओं और प्रत्यक्ष लाभांतरण (डीबीटी) लाभार्थियों को भी शामिल किया गया। आईपीपीबी ने महिलाओं के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हुए 6.57 करोड़ से अधिक खाते खोले हैं तथा 5.32 करोड़ से अधिक डीबीटी लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए, आईपीपीबी ने डोरस्टेप बायोमैट्रिक सत्यापन के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (डीएलसी) सेवा शुरू की है। देशभर में ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने के लिए आईपीपीबी द्वारा 24×7×365 संपर्क केंद्र उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें आईवीआर तथा 13 भाषाओं में एजेंट असिस्टेड सहायता के साथ-साथ ई मेल आधारित सहायता भी प्रदान की जाती है।

*****

अनुबंध - I

"इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक सेवा का विस्तार" विषय पर दिनांक 12.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4069 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	एक्सेस पॉइंट (डाकघर)	आईपीपीबी के ग्राहक	आईपीपीबी बैंकिंग आउटलेट
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	80	6,966	1
2	आंध्र प्रदेश	10,646	91,97,963	24
3	अरुणाचल प्रदेश	1,148	1,01,838	10
4	असम	4,062	47,07,932	26
5	बिहार	9,319	1,69,98,120	38
6	चंडीगढ़	48	71,146	1
7	छत्तीसगढ़	4,699	28,88,991	27
8	दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव	50	70,177	1
9	गोवा	259	65,801	2
10	गुजरात	8,834	44,53,036	31
11	हरियाणा	2,704	13,45,708	20
12	हिमाचल प्रदेश	2,793	8,50,313	12
13	जम्मू एवं कश्मीर	1,616	2,55,523	7
14	झारखंड	4,572	31,38,536	22
15	कर्नाटक	9,677	68,83,968	31
16	केरल	4,994	18,85,013	14
17	लद्दाख	119	8,568	1
18	लक्षद्वीप	10	1,062	1
19	मध्य प्रदेश	10,286	86,96,837	42
20	महाराष्ट्र	13,808	1,89,98,416	40
21	मणिपुर	714	3,45,755	9
22	मेघालय	932	2,67,724	8
23	मिजोरम	458	1,31,308	6
24	नगालैंड	403	1,72,833	9

25	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	473	6,50,879	2
26	ओडिशा	8,910	45,94,105	33
27	पुदुच्चेरी	96	1,05,986	2
28	पंजाब	3,805	11,64,983	22
29	राजस्थान	11,057	46,28,033	33
30	सिक्किम	212	16,403	1
31	तमिलनाडु	11,658	1,01,64,994	35
32	तेलंगाना	6,229	55,27,094	23
33	त्रिपुरा	735	1,08,570	5
34	उत्तर प्रदेश	17,933	2,18,18,542	73
35	उत्तराखंड	2,733	6,54,872	12
36	पश्चिम बंगाल	8,782	34,36,683	25
	कुल योग	**1,64,854**	**13,44,14,678**	**649**